भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 56

जिसका उत्तर सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा

56. श्री काली चरण सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजिटल लेन-देन, विशेष रूप से यूपीआई, आईएमपीएस और एनईटीसी फास्टैग के माध्यम से अभूतपूर्व वृद्धि का आकलन किया है और यदि हां, तो ऐसे आकलन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के मद्देनजर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और मापनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित आबादी के बीच डिजिटल भूगतान प्रणालियों को अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) क्या सरकार देश भर मे यूपीआई, आईएमपीएस और फास्टैग के लिए पहुंच और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग कर रही है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) पिछले पांच वर्षों में डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विकास और संवर्धन के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): डिजिटल भुगतान लेनदेन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, डिजिटल भुगतान जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ था, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 18,737 करोड़ हो गया, इस प्रकार 44% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) प्राप्त हुई है। हालांकि आईएमपीएस और एनईटीसी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है, देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन के समग्र विकास में यूपीआई प्रमुख प्रेरक शक्ति रहा है।

(ख): डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें डिवाइस बाइंडिंग, द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण, लेनदेन की सीमा और

जागरूकता अभियान शामिल हैं। एनपीसीआई ने क्यूआर कोड सुरक्षा पर जोर दिया है और गांवों में प्रशिक्षण आयोजित किया है, जबकि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन (1930) की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने नागरिकों द्वारा धोखाधड़ी वाले मोबाइल नंबरों की रिपोर्ट करने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) और "चक्षु" की शुरुआत की है।

(ग) से (ङ): डिजिटल भुगतान प्रणालियों (ग्रामीण और अल्पसेवित जनसंख्या सहित) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कई पहल की हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

i) निम्नलिखित वित्तीय परिव्यय के साथ रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम- यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना।

वित्तीय वर्ष	वित्तीय परिव्यय (करोड़)
2021-22	1,300 करोड़ रुपये
2022-23	2,600 करोड़ रुपये
2023-24	3,500 करोड़ रुपये

ii) टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई द्वारा जनवरी 2021 में भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) का परिचालन किया गया था, इन प्रयासों के कारण 30 नवंबर, 2024 तक 4.08 करोड़ टच पॉइंट्स लगाए गए हैं।

iii) एनपीसीआई ने कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में और स्मार्ट फोन न रखने वाले लोगों के लिए डिजिटल भुगतान लेनदेन की सुविधा हेतु यूपीआई 123पे और हैलो! यूपीआई जैसे नवोन्मेषी उत्पाद आरंभ किए हैं।

****